(d) The following steps have been taken to popularise khadi in the country including Gujarat:—

(i) Improvement in quality of raw-material through setting up of central sliver plants.

(ii) Improvement in quality of the yarn through introduction of high speed new model charkhas and S spindle charkhas for cotton & polyvastra; medlery & Bhageswari (2 spindle) charkhas for woollen etc.

(iii) Improvement in quality of fabric through improvement looms, processing etc.

(iv) Enabling institutions to set up khadi bhandars etc. by arranging finance from commercial banks, SIDBI etc.

(v) Continuing the rebate system as an incentive to buy khadi.

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

4139. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1980 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ग) ये उद्योग किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होता है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) औद्योगिक नीति 1980 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

अधिक रोजगार का सृजन करना,
औद्योगिक क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना,
पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना,
कृषि आधार को मजबूत करने के लिए कृषि उद्योग को प्राथमिकता देना,
उपभोक्ता संरक्षण,
आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देना,
अधिकतम उत्पादन करना और
अधिक उत्पादकता प्राप्त करना,
अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अनुसार कानपुर देहात, अल्मोड़ा, फैजाबाद, देवरिया, मथुरा, गोंडा, मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद, ललितपुर, खीरी नैनीताल, बरेली, बिजनौर इत्यादि जैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1991 से 1993 के दौरान कुल 53 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे। ये लाइसेंस धातुकर्मी उद्योग, ईंधन, वैद्युत उपकरण, दूरसंचार परिवहन, रसायन औषध और फेंसेज, कपड़ा, चीनी फर्मेन्टेशन उद्योग चमड़ा इत्यादि जैसे अनुसूचित उद्योगों से संबंधित विभिन्न मदों का निर्माण करने के लिए दिये गये थे।

क्योंकि एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में सामान्यतः 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं अतः उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

Allocation of Funds for Development of Rural Industries

4140. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI AAS MOHAMMAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased, to state:

(a) whether the Union Government have reduced the allocation for the development of rural industries during 1993-94 as compared to the last year as a result of which there has been an adverse impact on the development of rural industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount allocated separately during the last three years for the development of rural industries; and

(d) the reasons for reducing this amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M.

ARUNACHALAM): (a) to (d) No, Sir. The amount allocated, for Khadi and Village Industries Sector through Khadi and Village Industries Commission for the last three years for development of rural industries are given below:—

Year	Amount (Rs. in lakhs)
1992-93	193.00 (Actuals)
1993-94	208.00 (Actuals)
1994-95	214.00 (Budget Estimate)

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

4141. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या **प्रधान मंत्री** 11 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2363 के दिये गये उत्तर को देखेंगे कि और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने रुग्ण उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है/बंद किये जाने की संभावना है;

(ग) उनकी रुग्णता के प्रमुख कारण क्या हैं और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या उन रुग्ण एककों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन मामलों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को भेजा गया है और यदि हां, तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(च) गुजरात में किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के/उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय गुजरात/दो राज्य में अवस्थित थे। विगत तीन वर्षों के लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

		निवल लाभ/घाटा		
		1992-93	1991-92	1990-91
1.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	13177	5502	5727
2.	एन०टी०सी० (गुजरात) लि०	-8385	-3713	-2195

(ख) से (च) एन०टी०सी० (गुजरात) लि० एक रुग्ण उद्यम है एवं इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत कर दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के लिए प्रचालन अभिकरण की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 अप्रैल, 1994 को विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्रमिक संघ, प्रबन्धन तथा सरकार के प्रतिनिधियों में एन०टी०सी० के सभी कारखानों का पुनरुद्धार करने पर सहमति हो गई थी। पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, पुरानी प्रोद्योगिकी, श्रमिकों का बाहुल्य आदि रुग्णता के मुख्य कारण हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के अंतिम निर्णय की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है। वर्तमानः, गुजरात स्थित किसी सरकारी उद्यम के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।